६ नवभारत टाइम्स नई दिल्ली ९ फरवरी, १९८५

चावल की आड़ में जासूसी और जालसाजी

—आलोक मेहता—

नई दिल्ली, ८ फरवरी। जासूसी-कांड में पूर्वी यूरोपीय देशों के व्यापारिक संबंधों और गुप्तचरी की गतिविधियों का भंडाफोड़ होने के बाद अब इंटेलीजेंस ब्यूरो सोवियत संघ तथा अन्य कम्युनिस्ट देशों को बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात करने वाली कम्पनियों, उनके दलालों और राजनीतिज्ञों तथा राजनयिकों के जरिए हुए सौदों की गतिविधियों से छानबीन कर रहा है।

गुप्तचर एजेंसियों की प्रारम्भिक छानबीन से कुछ राजनयिकों और सत्ता में प्रभाव रखने वाले कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा चावल निर्यात के सौदों में कमीशन के रूप में लाखों रुपया लेने का चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। ये लोग रूस तथा अन्य कम्युनिस्ट देशों को बासमती चावल निर्यात करवाने का सौदा करवाते रहे हैं। चावल का व्यापार करने वाले बड़े-बड़े व्यापारी इन प्रभावशाली लोगों को संपर्क सूत्र बना कर 'बासमती' चावल का सौदा करते, लेकिन 'परमल' चावल भिजवाते रहे। इस तरह सीधे-सीधे लाखों रुपए की बचत होने पर व्यापारी से राजनीतिज्ञ और राजनयिकों को अच्छा खासा कमीशन मिलता रहा है।

गुप्तचर एजेंसियों के अधिकारी अब यह पता लगा रहे हैं कि कमीशन पाने वाले ऐसे नेता, प्रशासनिक अधिकारी और राजनयिक इन सौदों की आड़ में क्या सरकार की गोपनीय सूचनाएं बेचने का काम तो नहीं करते रहे हैं? बताते हैं कि साम्यवादी देशों के साथ सौदा पटाने वाले प्रभावशाली लोगों की सीधी पहुंच प्रधानमंत्री-निवास तक रही थी। अब उन्हें प्रधानमंत्री के दरवाजे तक फटकने नहीं दिया जाता है। इसी तरह भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री, भूतपूर्व सांसद, वरिष्ठ अधिकारी और भारत-सोवियत मैत्री संगठनों के महत्वपूर्ण पदों पर रहे अधिकारियों पर भी इन सौदों और साम्यवादी देशों के राजनयिकों के साथ घनिष्ठ संबंध रहने के तथ्य मिले हैं।

गुप्तचर एजेंसियां अभी इस गुत्थी को भी नहीं सुलझा पा रही हैं कि सोवियत संघ और अन्य कट्टर कम्युनिस्ट देश के राजनयिक किस तरह 'कमीशन' के रूप में लाखों रुपए बनाते रहे? क्या इसकी सूचना उनकी सर-

(शेष पृष्ठ ५ कालम एक पर)

चावल की आड़ में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कारों को रही है और ऐसा था तो इस धनराशि का उपयोग कहां होता रहा है?

एक रोचक तथ्य यह भी सामने आया है कि पिछले वर्ष केन्द्र के एक मंत्री ने अपने किसी परिचित व्यापारी को भी चावल-निर्यात का सौदा दिलवाने का प्रयास किया, लेकिन 'प्रभावशाली लोगों' ने उनकी भी नहीं चलने दी थी।

बताया जाता है कि गुप्तचर एजेंसियां सोवियत संघ के साथ कपड़ों का व्यापार करने वाली एक सबसे बड़ी फर्म की गतिविधियों की भी छानबीन कर रही हैं, क्योंकि इस फर्म के एक सिनियर भागीदार (पार्टनर) के उच्चाधिकारियों के साथ संपर्क रहने की आशंका भी है। इंटेलीजेंस ब्यूरो इस पार्टनर की गतिविधियों पर पिछले ६ महीने से नजर रखे हुए है। इस फर्म के प्रबंधकों ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं से बड़े अच्छे संबंध रखे हैं। इसलिए गुप्तचर एजेंसियां सारे प्रामाणिक तथ्य मिलने पर ही कार्रवाई करना चाहती हैं।

याद रहे, साम्यवादी देशों के [illegible]

[illegible] पत्नी से बहुत पूछताछ की गई थी, लेकिन तब इस तरह के जासूसी जाल के सारे सूत्र नहीं मिल पाए थे।